मध्यप्रदेश शासन
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन

e-Gov-7

क्रमांक/ एफ 8-1/2009/56, भोपाल, 28 मार्च, 2013

प्रति,

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव
मध्यप्रदेश शासन
समस्त विभाग
मंत्रालय, भोपाल।

2. कलेक्टर
समस्त, मध्यप्रदेश।

विषय : स्टेट पोर्टल एवं स्टेट सर्विस डिलेवरी गेटवे परियोजना के संबंध में।

परियोजना पृष्ठभूमि -

1/- प्रदेश के समस्त नागरिकों को त्वरित, पारदर्शी, मितव्ययी एवं सुविधाजनक रूप से तथा सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए उनके निकटतम स्थान से लोक सेवाऐं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राष्ट्रीय ई-गवर्नेन्स योजना के अंतर्गत 31 मिशन मोड परियोजनाओं की संकल्पना एवं क्रियान्वयन किया जा रहा है जिनमें स्टेट पोर्टल एवं स्टेट सर्विस डिलेवरी गेटवे परियोजना प्रमुख है। वस्तुतः स्टेट डेटा सेन्टर, स्टेट वाईड एरिया नेटवर्क तथा कॉमन सर्विस सेन्टर परियोजनाओं की भांति यह परियोजना भी देश एवं प्रदेश में आई.टी. की अधोसंरचना के विकास को लक्षित कर क्रियान्वित की जा रही है ताकि इस अधोसंरचना का लाभ क्षैतिज एवं समानान्तर रूप से सभी प्रकार के भौगोलिक मुख्यालयों, विभागों एवं कार्यालयों को प्राप्त हो सके। इस परियोजना की लागत 10.84 करोड़ रूपये है तथा इसकी पूँजीगत लागत भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। परियोजना की नोडल ऐजन्सी मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम है तथा मैप-आईटी द्वारा परियोजना के क्रियान्वयन में तकनीकी सहयोग किया जा रहा है। मध्यप्रदेश में परियोजना के निजी सहभागी के रूप में

टीसीएस लिमिटेड कार्यरत है जो परियोजना के विकास, क्रियान्वयन तथा क्रियान्वयन प्रारम्भ होने के 3 वर्षों तक रखरखाव आदि से संबंधित कार्य करेगी। भारत सरकार द्वारा इस परियोजना की अवधि मार्च 2017 रखी गई है।

परियोजना के प्रमुख उद्देश्य

- नागरिकों को उनके द्वार पर अथवा उनके निकटस्थ नागरिक सुविधा केन्द्र पर सूचनाऐं एवं लोक सेवाऐं प्रदान करना।
- नागरिकों को शासकीय कार्यालयों में सेवा प्राप्त करने के लिए कम से कम आवागमन करना पड़े, ऐसी व्यवस्था करना।
- नागरिक सुविधा केन्द्र, स्टेट वाईड एरिया नेटवर्क तथा स्टेट डेटा सेन्टर जैसी आई.टी. अधोसंरचनाओं का ईष्टतम उपयोग करना।
- नागरिकों का शासकीय अधिकारियों के साथ सेवा एवं सूचनाऐं प्राप्त करने के संबंध में प्रत्यक्ष भेंट की आवश्यकता को न्यूनतम करना।
- नेशनल पोर्टल तथा नेशनल सर्विस डिलेवरी गेटवे की तर्ज पर सम्पूर्ण राज्य के लिए एकीकृत शासकीय वेब इंटरफेस प्रदान करना।
- अधिकाधिक इलेक्ट्रॉनिक संव्यवहारों के माध्यम से नागरिकों एवं अधिकारियों दोनों के लिए समय, शक्ति एवं संसाधनों की बचत सुनिश्चित करना।
- विभिन्न विभागों की वेबसाईट्स को भारत सरकार की गाईड लाईन के अनुरूप व्यवस्थित करना।

परियोजना के प्रमुख अंग

1. स्टेट पोर्टल

शासकीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों तथा राज्य शासन द्वारा नागरिकों को उपलब्ध कराई जा रही विभिन्न सुविधाओं की जानकारी नागरिकों तक पहुँचाने के लिए वर्तमान युग में इंटरनेट एक सशक्त माध्यम है। भारत सरकार द्वारा भी एनआईसी के सहयोग से एक एकीकृत पोर्टल www.india.gov.in, तैयार किया गया है, जिसके माध्यम से केन्द्र शासन के विभिन्न विभागों, राज्य सरकारों, नागरिकों एवं व्यवसायियों को एकल खिड़की व्यवस्था की भांति सिंगल वेब इंटरफेस प्रदान किया गया है। पोर्टल पर जानकारियों और सेवाओं को एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है। मध्यप्रदेश में भी वैसे तो विभिन्न विभागों एवं एजेन्सियों द्वारा अपनी योजनाओं एवं कार्यक्रमों की जानकारी नागरिकों को प्रदान करने के लिए पृथक-पृथक वेबसाईट्स का निर्माण किया गया है जोकि या तो एनआईसी के